

## न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या-158/2013-14

अन्तर्गत धारा-333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री भगत सिंह

बनाम

श्री विरेन्द्र सिंह चौहान एवं अन्य

उपस्थिति: श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री रविन्द्र सिंह।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा-मेहूवाला माफी, परगना केन्द्रीय दून,  
तहसील व जनपद देहरादून।

### आदेश

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा निगरानी संख्या-97/2012-13 विरेन्द्र सिंह चौहान बनाम प्रेम सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 23-09-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अवर न्यायालयों के अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन था कि अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन निगरानी में दिनांक 23-09-2013 में उत्तरदाता संख्य-1 के अधिवक्ता द्वारा तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया परन्तु आदेश पंजिका में दिनांक 23-09-2013 यह आदेश पारित किया गया कि " आज पत्रावली प्रस्तुत। निगरानीकर्ता हाजिर, विपक्षीयण पर समन तामील नहीं पुनः समन भेजे जायं। पत्रावली वास्ते सुनवाई 11-12-2013 को पेश हो। पक्षकार विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखें तथा विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द न करें।" उक्त आदेश पक्षकारों को सुने बिना पारित किया गया है तथा उत्तरदाता संख्या-1 की ओर से बिना प्रार्थना पत्र दिये ही यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये हैं। अतः निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 23-09-2013 निरस्त कर दिया जाय।

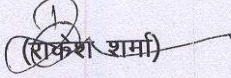
अधिवक्ता प्रतिपक्षी का कथन था कि आदेश दिनांक 23-09-2013 अन्तरिम आदेश है, और अन्तरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।

अवर निगरानी न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 23-09-2013 बिना किसी के प्रार्थना पत्र के पारित किया गया है। अवर न्यायालय में आदेश दिनांक 23-09-2013 रिकॉल करने हेतु अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या-1 की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 09-06-2014 प्रस्तुत किया गया है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया आदेश दिनांक 23-09-2013 अन्तरिम आदेश प्रतीत होता है और अन्तरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09-06-2014 का निस्तारण अभी नहीं हुआ है। निगरानी बलयुक्त न



होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय प्रतिउत्तरदाता संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09-06-2014 का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत निगरानी को गुणदोष के आधार पर निर्णित करें।

दिनांक: 08 जनवरी, 2015

  
अध्यक्ष।